



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-७] रुड़की, शनिवार, दिनांक ०७ जनवरी, २००६ ई० (पौष १७, १९२७ शक सम्वत) [संख्या-०१

विषय-सूची

प्रत्येक माग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक बंदा रु०
सम्पूर्ण गजट का भूल्य	—	3075
माग १-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, रथान-नियुक्ति, रथानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	1-15	1500
माग १-क-नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	—	1500
माग २-आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	875
माग ३-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइल एरिया, टाउन एरिया एवं निवार्चन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अध्याय जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
माग ४-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	—	975
माग ५-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	—	975
माग ६-बिल, जो मार्त्रीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
माग ७-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निवार्चन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	—	975
माग ८-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	— १	975
स्टोर्स पर्सेज-स्टोर्स पर्सेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि	—	1425

भाग १

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार तौर दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2005 ई०

संख्या 2157 / VIII / 285—श्रम / 2001—श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण अधिनियम, 1965 (च०प्र० अधिनियम संख्यांक 14, सन् 1965) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्रमायुक्त, उत्तरांचल को अपने पद के अतिरिक्त श्रम कल्याण आयुक्त, उत्तरांचल के रूप में भी नियुक्त करने की सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्छाल,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

अधिसूचना

27 दिसंबर, 2005 ई०

संख्या 3428 / XX-1 / 426 / निर्माण / 2003—मूर्मि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1233 / आठ—य०भ०ज०आ० / देहरादून / 2005, दिनांक 06 जुलाई, 2005 के क्रम में राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित गृमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, अर्थात् पुलिस मुख्यालय (अधिसूचना / सुरक्षा), देहरादून हेतु भवन सनिर्माण के लिए आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन देहरादून के कलेक्टर को यह निर्देश देते हैं कि उक्त गृमि का अर्जन करने की कार्यालयी करें।

2—चूंकि, राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह सामला अत्यावश्यक है इसलिये यह उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि यथापि धारा 11 के अधीन कोई अभिनियम नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ देहरादून के कलेक्टर धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अन्दर संगत मूर्मि पर कामा कर सकते हैं :

अनुसूची

जिला	परगना	ग्राम	खसरा (प्लाट) नं०	लगभग क्षेत्रफल		चौहड़ी
				एकड़	हेक्टेअर में	
१	२	३	४	५	६	
देहरादून	केन्द्रीय दून	छालनवाला	8 चन्द्र रीड	1.47 एकड़ या 5953 हेक्टर या या 7.91 बीघा	पूर्व—लकड़ी रोड पश्चिम—मूर्मि श्री समाचल्ला उत्तर—चन्द्र रोड दक्षिण—वैल्हम स्कूल	

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—जनपद देहरादून में पुलिस मुख्यालय (अधिसूचना / सुरक्षा) हेतु भवन निर्माण हेतु।

टिप्पणी—उक्त मूर्मि के नक्सों का कलेक्टर देहरादून के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीकण किया जा सकता है।

आज्ञा से,

एस० के० दास,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3428/XX-1/426/Construction/2003, dated 27 December, 2005 for general information :

NOTIFICATION

December 27, 2005

No. 3428/XX-I/426/Construction/2003—In continuation of Notification no. 1233/आर— विभूषणोऽपि / देहरादून / 2005, Issued under sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1, 1894), the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely for construction of Police Headquarters (Intelligence/Security) Building, District Dehradun and under section 7 of the said Act to direct the Collector of Dehradun to take action for the acquisition of the said land.

2. The Governor, being satisfied that the case is one of urgency in further pleased under sub-section of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Dehradun though no award under section 11 has been made may on the expiration of 15 Days from the publication of Notice mentioned in sub-section (1) of the section of taking possession of the said land mentioned in the Schedule for the said public purposes :—

SCHEDULED

District	Pargana	Village	Plot No.	Approximate area in Acres/Hectares	Remark
1	2	3	4	5	6
Dehradun	Central Dun	Dalanwala	8 Chander Road	1.47 Acres or 5953 Hectares or 7.91 Beegha	East—Laxmi Road West—Land of Sir Sabha-Ulla North—Chander Road South—Welhem School

For what purpose required— Police Headquarter Building (Intelligence/Security) 8 Chander Road, Dehradun.

NOTE— A plan of the site land may be inspected by the interested persons in the office of the Collector, District Dehradun.

By Order,

S. K. DAS,
Principal Secretary.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

२८ दिसम्बर, २००६ ई०

संख्या यू०आ० ६२/१८(१)/२००५—उत्तर प्रदेश लोकघन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९७२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २३, रान् १९७२) (उत्तरांचल में यथा प्रदृश्ट) की धारा २ के खण्ड (क) के अधीन शबित का प्रयोग करते हुये राज्यपाल “उत्तरांचल राज्य मत्स्य पालक विकास अभियान”, देहरादून को, जिस पर राज्य सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण है, उक्त अधिनियम के लिए नियम के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं।

आज्ञा से,

नूप सिंह नपलच्चाल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O. 62(1)/18(1)/2005, dated 28 December, 2005 for general information :

NOTIFICATION

December 28, 2005

No. U.O. 62(1)/18(1)/2005—In exercise of the powers under clause (a) of section 2 of the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972, (U.P. Act no. XXIII of 1972) (as applicable in Uttarakhand), the Governor is pleased to specify the "Rajya Matsya Palak Vikas Abhikaran" which is owned and controlled by the State Government, as Corporation, for the purpose of the said Act.

By Order,

NRIP SINGH NAPALCHYAL,
Principal Secretary.

कृषि एवं विषणन अनुभाग—1**कार्यालय आदेश**

25 नवम्बर, 2005 ई०

संख्या 1508 / XIII / 2005-3(5) / 2001—कृषि विभाग, उत्तरांचल में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—1, रोकशन "सी" (सांखियकी शाखा) रोकशन सेवा श्रेणी—2 (सांखियकी शाखा) में प्रो-नियमित के लिये आरक्षित रिवितायों में नियमित नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा समूह 'ख' सेवा नियमावली, 1995 (उत्तरांचल में अनुकूलित/उपान्तरित आदेश, 2002) के सुरांगत नियमों एवं उत्तर प्रदेश लोक रोका आयोग सपरामर्श वयनोनाहि (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथा संशोधित) के प्राचीनित प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिहार के परामर्श के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—1 (सांखियकी शाखा) के कर्मियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित घयन वर्ष की रिवितायों में वेतनमात्र रु 8,000-275-13,500 में नियमित नियुक्ति हेतु अनुमोदन करते हुए उन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखकर उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/स्थान पर तैनात किये जाने को सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र०सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम व वर्तमान तैनाती	एतद्वारा प्रस्तावित तैनाती	घयन वर्ष
1.	श्री प्रेम प्रकाश शाह, वर्ग—1, कृषि निदेशालय, उत्तरांचल	कृषि निदेशालय, देहरादून में रिक्त सहायक निदेशक, सांखियकी के पद पर	2003-04
2.	श्री दुर्गाराम आर्य, वर्ग—1, संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्दानी	संयुक्त कृषि निदेशक, कार्यालय कुमाऊँ मण्डल, हल्दानी में रिक्त सहायक निदेशक, सांखियकी के पद पर	2003-04

रावित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के पदों पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रभानक शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

अज्ञा से,

ओम प्रकाश,
सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग—1**कार्यालय—ज्ञाप**

21 नवम्बर, 2005 ई०

संख्या 4095 / सात / 05 / 128—स्वयंग / 2004—विद्वित संख्या 161 / प्र०सं० / औ०वि० / 2002, दिनांक 09 अगस्त, 2002 के द्वारा उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिंग (सिडकुल) के निदेशक मण्डल का गठन किया गया है। कार्यालय—ज्ञाप संख्या 63 / ज०सं० / औ०वि० / 2003, दिनांक 23 सितम्बर, 2003 के द्वारा निदेशक मण्डल में अन्य निदेशकों के साथ-साथ निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सचिवाध्यक्ष नामित किये गये हैं :—

1. डा० आर० एस० टोलिया, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन अध्यक्ष।
 2. श्री संजीव चोपडा, सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन उपाध्यक्ष।

उपर्युक्त क्रमांक-1 पर उल्लिखित डा० आर० एस० टोलिया के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो जाने के फलरवरुप उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० (सिड्कुल) के निदेशक मण्डल में शासन द्वारा निम्नांकित को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया जाता है :-

1. श्री एम० रामचन्द्रन, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन अध्यक्ष।
 2. श्री संजीव चोपडा, सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन उपाध्यक्ष।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे तथा निदेशक मण्डल के गठन शम्भन्धी आदेश संख्या 161/प्र०स०/ओ०वि०/2002, दिनांक 09 अगस्त, 2002 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संजीव चोपडा,
सचिव।

नियोजन अनुभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर, 2006 ई०

संख्या 556/एक(49)/04-XXVI/2005-उत्तरांचल राज्य की मानीरथी नदी धाटी और टिहरी बांध के ऊपरी और निचली और तथा इसके जलागम और प्रभावी क्षेत्रों के विशेष सन्दर्भ में नदी धाटी के स्थायी विकास और समुचित प्रबन्ध हेतु "उत्तरांचल नदी धाटी (विकास और प्रबन्ध) अधिनियम, 2005" प्रबलित है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भागीरथी नदी धाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अधिनियम में निहित व्यवस्थानुसार कार्यों के संचालन हेतु विभिन्न अधिकार मानीरथी नदी धाटी विकास प्राधिकरण को प्रदत्त हैं। मात्र मुख्यमंडी जी की अध्यक्षता में दिनांक 20-05-2005 को "मानीरथी नदी धाटी विकास प्राधिकरण" की बैठक हुई थी, जिसके आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपाना यह निर्णय लिया गया है कि कार्य की व्यवहारिकता, सुगमता एवं सुविधा आदि के दृष्टियत अधिसूचना संख्या 416/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, दिनांक 27 जनवरी, 2005 द्वारा प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकारों में से निम्नांकित अधिकार महाभिषेक श्री राज्यपाल प्राधिकरण की कार्यपालिका सभिति को एतद्वारा प्रतिनिधानित किये जाने की शर्ह स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1-धारा 4 (2)-अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार।
- 2-धारा 5 (1)-प्राधिकरण में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार।
- 3-धारा 6 (1)-तकनीकी सलाहकारों/संस्थाओं को नियुक्त करने का अधिकार।
- 4-धारा 8 (1) (व)-जलागम क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन कोष/आपात समूह व आपदा कोष की स्थापना और रख-रखाव करना।

(छ) नदी धाटी में समुचित स्थानों पर प्रभावी शिकायत निवारण प्रक्रियों की स्थापना और रख-रखाव करना।

5-धारा 9 (1)-अधिनियम और इसके अधीन बने विभिन्नों के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी शक्तियाँ जैसी आवश्यक और आनुषंगिक हों, कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन।

6-धारा 9 (2)-उपधारा (1) के प्राविधानों की व्यापकता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना निम्नलिखित शक्तियाँ-

(ख)-प्राधिकरण की महायोजना में उल्लिखित किसी विकास की योजना को अनुमोदित या निरस्त करना तथा ऐसी महायोजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व नदी धाटी के जलागम क्षेत्र में अन्य अधिकरणों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों का धारा 11 की उप धारा (3) से (5) के अनुसार विनियमन करना।

(ग)-किसी भी क्षेत्र के लिए निर्धारित नीतियों के अनुपालन हेतु सम्बन्धित अन्य विकास एजेंसियों को निर्देश देना।

(घ)–नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी संगठन या किसी अन्य एजेंसी से सहायता लेना।

7–धारा 9 (2)–प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना महायोजना में उल्लिखित कोई भी प्राथमिक या अन्य कार्य या किसी विकास योजना को आरम्भ नहीं किया जायेगा।

8–धारा 9 (3)–महायोजना में कोई भी परिवर्तन, प्राधिकरण की अनुमति से ही किया जायेगा।

9–धारा 9 (4)–प्राधिकरण को उसके कार्यों और नीतियों को लागू करने में राज्य की परिषदों सहित सभी सम्बंधित विभाग, अपने प्रमुखों के माध्यम से, उसके साथ समन्वय करेंगे और प्राधिकरण या कार्यपालिका समिति द्वारा अपनी शर्तों और इक्षित तथा मुगलान के आधार पर सरकार के किसी विभाग की सेवाओं की मांग करना वैध होगा।

10–धारा 10 (1)–प्राधिकरण पूर्व में किये गये भौगोलिक क्षेत्र विकास योजना निर्धारण करने के पश्चात् यथाशीघ्र नदी धाटी के समय स्थानी विकास हेतु एक महायोजना की तैयारी करेगा या करवायेगा।

11–धारा 11 (3)–प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् उस क्षेत्र में जिसके लिए ऐसे प्राधिकरण का गठन हुआ हो, किसी भी व्यक्ति या संस्था जिसमें राज्य के विभाग या प्राधिकारी भी सम्मिलित होंगे तथा लोक या निजी क्षेत्र के उपकरण के द्वारा भूमि के विकास सम्बन्धी कार्यों को ना तो किया जायेगा और ना ही करवाया जायेगा या जारी रखा जायेगा, जब तक कि ऐसे विकास हेतु प्राधिकरण से लिखित रूप में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुमति ना प्राप्त कर ली गयी हो।

12–धारा 13 (1)–प्राधिकरण की नियंत्रण, प्राधिकरण या कार्यपालिका समिति के नियंत्रणसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य लघु बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो, में खाता खोल कर जमा वीं जायेगी और उसका संचालन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी या इस हेतु प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

13–धारा 13 (2)–प्राधिकरण, यथावश्यक स्थलों पर यथावश्यक संस्थाएं में प्राधिकरण के खाते खोल सकता है।

14–धारा 13 (3)–प्राधिकरण यथा निर्धारित रूप में और यथा समय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय तथा व्यय दर्शाते हुए बजट तैयार करेगा और प्रतिवर्ष 15 फरवरी से पूर्व इसकी एक प्रति प्राधिकरण की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत करने के लिए, राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु अर्हवित करेगा।

15–धारा 14 (2)–प्राधिकरण के वार्षिक लेखा की सेवापरीक्षा, अनुभवी चार्टर्ड एकाउटेंट या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समान पदधारक व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

16–धारा 15–प्राधिकरण, वर्ष के दौरान सम्पन्न, अपनी गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उस प्रतिवेदन तैयार करेगा और उस प्रतिवेदन को राज्य सरकार को तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार द्वारा विभिन्निष्ट प्रारूप में और तिथि से पूर्व केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

17–धारा 16–प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत, प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सभी युक्तिशुद्ध समग्रों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकता है और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों के प्रयोग या कार्य-निष्पादन हेतु कोई भी विधिसम्मत कार्य या सर्वेक्षण, खोज और सर्वेक्षण, प्रारम्भिक या अनुष्ठानिक रूप से कर सकता है।

18–धारा 20–प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों की स्थापना।

19–धारा 25–प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के इस्तासार से लिखित शिकायत के बिना कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

20–धारा 28 (1)–इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध, कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, प्राधिकरण या इसके द्वारा इस हेतु सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या निर्धारित शर्तों पर या शमन-फीस के मुगलान की शर्त पर शमनीय हो सकेगा।

21–धारा 31 (1)–किसी अन्य विधिक के होते हुए और सांसद द्वारा खनिज विकास सम्बन्धी विधि द्वारा किसी प्रतिबन्ध के होते हुए भी प्राधिकरण, नदी धाटी में खनिज अधिकारों हेतु उपकर लगा सकेगा।

आज्ञा से,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव।

दन एवं पर्यावरण अनुभाग—१

संकल्प

उत्तरांचल वृक्षारोपण नीति, 2005

१२ दिसंबर, २००५ ₹०

संख्या 706 / X-2-005-१(21) / 2005-

१. प्रस्तावना

- 1.1 प्रदेश में वृक्षरोपण कार्य का एक पुराना इतिहास है। स्वतंत्रता से पूर्व प्रदेश के बनों की सधनता के कारण वृक्षरोपण केवल सीमित क्षेत्रों में ही अधिकांश तौर पर बीजरोपण तथा कुछ क्षेत्रों में पौधारोपण के माध्यम से ही किये जाते रहे। स्वतंत्रता के पश्चात् विशेष रूप से तीसरी पंचवर्षीय योजना से वृक्षरोपण की आवश्यकता महसूस करते हुए बड़े पैमाने पर वृक्षरोपण योजनायें बनाई गईं।

1.2 उत्तरांचल वन विभाग जो उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का ही अंग था, उतना ही पुराना है जिसना भारतवर्ष में बनों का वैज्ञानिक प्रबन्धन। उत्तरांचल के गठन के समय वन विभाग, उत्तरांचल द्वारा कार्य की सुगमता को दृष्टिगत रूप से हुए लगभग वे ही नीतियाँ स्वीकार की गई जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित थीं। अब उत्तरांचल को बने हुए लगभग साढ़े चार वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, भारत सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई जो उत्तरांचल सहित सभी राज्यों में लागू है। राज्य में भैदानी से लेकर हिमाल्यादित बोटियों वाले क्षेत्रों के कारण वानस्पतिक विविधता है, यहाँ के वन उत्तरांचल राज्य के राष्ट्र-साथ पूरे देश के पारिस्थिकी एवं पर्यावरण को संतुलित करते हैं। इस आलोक में सत्तरांचल की वर्ष 2001 में राज्य वन नीति प्रतिपादित की गई, वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में वृक्षरोपण की विभिन्न योजनाएं सञ्चालित की जा रही हैं, उदाहरण के लिए ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, भूग्री संरक्षण, नगर विकास, जलाशय विभाग व्यापक पैमाने पर वृक्षरोपण करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न गैर सरकारी संगठन (NGOs) भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षरोपण करते हैं। उक्त सभी विभागों द्वारा कराए जा रहे वृक्षरोपण योजनाओं में समरूपता के दृष्टिकोण से एक सभी वृक्षरोपण नीति लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

2. वृक्षारोपण नीति की दृष्टि (Vision)

आधुनिक दृक्षारोपण तकनीकी हारा प्रदेश के बन द्वेष गे तथा विद्यमान बनों के धनत्व/वानस्पतिक विद्य में चृढ़ि कर प्रदेश की जनता की मूलगृह आवश्यकताओं की सतत पूर्ति करते हुए प्रदेश, देश एवं विश्व को पर्यावरणीय संविधायें उपलब्ध करना।

३. मूल उद्देश्य

- 3.1 प्रदेश के अन्तर्गत विद्यमान वन मूर्मि एवं गैर वन मूर्मि पर वृक्षारोपण हेतु विभिन्न विभागों/ संस्थाओं द्वारा बलाई जा रही समस्त योजनाओं को समन्वित कर समरूपता लाना;

3.2 रामस्त प्रकार की अवनत व रिक्त वन मूर्मि में वनरस्पति में वृद्धि कर वनों के घनत्व/कुल वानस्पतिक निधि में वृद्धि करना;

3.3 ग्रामीणों की ईंधन की लकड़ी, वारा, लघु वन उपज एवं इमारती लकड़ी की स्थानीय घरेलू गांग की पूर्ति हेतु संवित प्रजातियों का बयन कर रोपण करना;

3.4 प्राकृतिक वनों में वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों के प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित कर इन्हें विकसित करने हेतु विशेष उपाय करना;

3.5 वृक्षारोपण कार्य को गरीब-निर्वल वर्ग के लोगों के लिए रोजगार-परक बनाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपाय करना;

3.6 उपरोक्त सिद्धान्तों की प्रतिपूर्ति के लिये वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देते हुए इनका वानस्पतिक परिवर्णनियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वयन करना;

4. पञ्चमी

- 4.1 उत्तरांचल मारुत उपमहाद्वीप की अनेक महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है, इन नदियों ने हमारी सम्यता को एक विशिष्ट पहचान दी है। वृक्षारोपण का एक प्रमुख उद्देश्य स्वच्छ बातावरण बनाये रखते हुए इसके माध्यम से इन महत्वपूर्ण नदियों के घल समेट सेत्र की हाइड्रोलौजी (Hydrology) संतुलित रखना है, जिससे

बहुमूल्य मिट्टी की चपरी उपजाऊ सतह का कारण रोका जा सके तथा जल की पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता में उपलब्धता करी रहे;

- 4.1.1 आधुनिक तकनीकी से वृक्षारोपण द्वारा वर्नों में सम्बद्धन कार्य से अपने भू-भाग का एक बड़ा हिस्सा हरित आवरण के रूप में बनाये रखने से जहां उत्तरांचल जैसे राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा अंश व्यय होता है, वहीं इन वर्नों के दोहन पर विभिन्न प्रतिबन्धों के कारण इनका सीधा लामा स्थानीय समुदायों को नहीं मिल पाता है;
- 4.1.2 ऐसी बनावली के पर्यावरणीय लाभ पूरे क्षेत्र व राष्ट्र को प्राप्त होते हैं, जबकि इसे बनाये रखने में यहाँ के स्थानीय समुदायों को आर्थिक विकास के अनुपलब्ध अदसरों के सापेक्ष अप्रत्यक्ष मूल्य नुकाना पड़ता है;
- 4.1.3 यह उचित होगा कि उत्तरांचल राज्य के वर्नों द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान कर केन्द्र से राज्यों को दिये जाने वाले विभिन्न कोषों के अंश निर्धारण में इसका भी पूर्ण संज्ञान लिया जाए;
- 4.1.4 क्योटो संधि (प्रोटोकॉल) द्वारा परिकल्पित वलीन डेवलपमेन्ट मैकेनिज्म (C.D.M.) व्यवस्था के अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट्स (Carbon Credits) प्राप्त करने हेतु परियोजनायें तैयार की जायें।
- 4.1.5 वन आवरण में वृद्धि भूल्यतः दो प्रकार से की जा सकती है :

(1) वन क्षेत्र में वृद्धि;

(2) विद्यमान वर्नों के घनत्व/समय वन निधि (ग्रौईंग स्टॉक) में वृद्धि।

उत्तरांचल पूर्व से ही वन बहुमूल्य दोष है, प्राच्य में वन प्रबन्ध की नीतियों के अन्तर्गत आवरण वृद्धि का आधार भूल्यतः प्राकृतिक पुनरोत्पादन रहा है, परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् बड़े पैमाने पर कृत्रिम रोपण की योजनायें कार्यान्वयन तुझे हैं। विभिन्न कार्य योजनाओं के अन्तर्गत इन दोनों विधियों से पुनर्जनन कार्य का प्राविद्यान किया गया एवं तादनुसार कार्य सम्पादित किये गये। वर्ष 1980 से 90 के दशक में कृत्रिम वृक्षारोपण वृहद रूप से सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में लागू हुई। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के वृक्षारोपण स्वापित किये गये। पर्यावरण भू-भाग में इसके अतिरिक्त नदी धारी जलागम क्षेत्रों के उपचार संबंधी परियोजनाओं में भी प्रधार मात्रा में वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

- 4.2 उत्तरांचल के गठन से पूर्व विश्व बैंक पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के दौरान यह अनुभव किया गया कि वृक्षारोपणों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु इनमें गुणात्मक सुधार के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है, इस परिवेश में यह आवश्यक है कि नीति में वृक्षारोपण हेतु तकनीकी पहलुओं के साथ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का भी समावेश किया जाय ताकि वृक्षारोपण की सफलता तथा उत्पादन दोनों में ही वृद्धि हो सके;
- 4.3 प्रारम्भिक दशकों में वृक्षारोपण कार्य बहुत अल्प पैमाने पर किये जाते थे। ये वृक्षारोपण अधिकांशतः अच्छी तश्चा सुरक्षित भूमि पर गहन देखमाल के अन्तर्गत होता था, जिसमें इनकी नुणात्मक सफलता सुनिश्चित रहती थी। वर्तमान में अब केवल अवान्त एवं अनुपयुक्त क्षेत्र ही रोपण के लिए उपलब्ध होते हैं जिनकी स्थलीय गुणवत्ता (Site Quality) अच्छी नहीं है; जैविक दबाव अत्यधिक है तथा अधिकतर क्षेत्र में नमी बहुत कम है, ऐसी रिथित में पुरानी बीजारोपण अथवा पौधारोपण की तकनीक के सापेक्ष अब भी पहले अपनाने पर विचार की आवश्यकता है, यद्यपि पुनरोत्पादन हेतु कई स्थानों पर प्राकृतिक रूप से ऊट स्टॉक उपलब्ध होता है, परन्तु अधिक जैविक दबाव के कारण पुनर्जनन नहीं हो पाता है, ऐसे क्षेत्रों में प्रभावी एवं दीर्घकालिक सुरक्षा की आवश्यकता है;
- 4.4 राज्य के अन्तर्गत वर्तमान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम पुनरोत्पादन हेतु आरक्षित वन, सिविल, सौयम वन, पंचायती वन, सामूहिक एवं निजी बंजर भूमि, साढ़क, नहर तथा रेलवे की पटिट्यां आदि प्रकार की भूमि उपलब्ध होती है। आरक्षित वर्नों के अवनता/खाली क्षेत्रों में विभिन्न कार्य योजनाओं के अन्तर्गत पुनरोत्पादन, हेतु क्षेत्र इंगित रहते हैं तथा योजनाबद्ध तरीके से इनका उपचार किया जाता है, परन्तु सिविल सौयम वन तथा अन्य प्रकार की भूमि पर वृक्षारोपण हेतु इनका सधन एवं दूरगामी प्रबन्ध आवश्यक है;
- 4.5 अधिकतर वन/वृक्षारोपण क्षेत्र अत्यन्त आबादी से धिरे हुए हैं जिनमें ईंधन, चारा एवं चराई का अत्याधिक दबाव होता है, जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण की संख्या में वृद्धि हो रही है जिसमें चराई का दबाव बढ़ रहा है, ऐसी रिथित में कोई भी पुनरोत्पादन कार्य की सफलता बिना आसपास के निवासियों के सहायोग लिये संभव नहीं है, अतः यह कार्य जन आदोलन के रूप में जन सहयोग/सहभागिता के माध्यम से ही सम्पादित किया जा सकता है।

- 4.6 उत्तरांचल की विशिष्ट भौगोलिक एवं टोपोग्राफिकल विविधता के कारण बनस्पतिक संरचना में भी प्रबुर विविधता है। भैदानी मू—भाग में साल, शीशम से लेकर पर्वतीय क्षेत्र में चौड़, बांज आदि के साथ उच्च स्थलीय पर्णपाती प्रजातियां विद्यमान हैं; साथ ही बहु—उपयोगी प्रजातियां विभिन्न वितानों (Storeys) में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। इनमें कई प्रजातियों का उपयोग स्थानीय लोगों के साथ—साथ उद्योगों द्वारा भी किया जाता है, अतः वृक्षारोपण की नीति में इस बहु—आयामी उपयोग को भी दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है;
- 4.7 प्रदेश वन्य जन्मु बाहुल्य क्षेत्र है एवं इनके संरक्षण में अग्रणी है, इस जैव विविधता को बनाये रखने में वनों का संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही वन्य पशुओं की उपयोगिता को भी दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त आवरण, संरक्षण / विकास पर ध्यान देना अत्यावश्यक है:
- 4.8 पुनरोत्पादन/कृत्रिम वृक्षारोपण कार्यों को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने हेतु राज्य/केन्द्र सरकार की विभिन्न वित्तीयों द्वारा विविध योजनाओं में यथापि उद्देश्यों की विविधता होती है, परन्तु वृक्षारोपण क्षेत्रों की समय रूप से सफलता को उच्च प्राप्तिकता दी जाती है। इनके प्राविद्यानां में एक समन्वयन आवश्यक है, इसके लिए विभिन्न प्रजातियों के रोपण के तकनीकी मापदण्ड, विविध कार्यों की दरे, संरक्षण/सुरक्षा अवधि तथा तकनीकी एकलूपता की आवश्यकता है। इन सब आयामों में नवीनतम तकनीकी, यथा पौध तैयार करने की रुट ट्रैनर विधि, ब्लोनल तकनीक आदि को व्यापक पैमाने पर अपनाना आवश्यक है;
- 4.9 राज्य का तराई, भावर क्षेत्र उत्पादन वानिकी हेतु अग्रणी रहा है। यहां से ही वन्य उत्पादन, विभिन्न काष्ठ—आधारित उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। इन कार्यों में तराई क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर अनुपयोगी घासों पर नियंत्रण की विधियों में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव लाना भी श्रेयस्कर होगा। उत्पादन वानिकी में प्रजाति वयन, प्रबन्ध नीति परिवर्तन तथा उपयोग की दृष्टि से अधिक संरपादन को लक्षित करना अपरिहार्य होगा;
- 4.10 हिमालय क्षेत्र मू—गर्भीय व ढाल की दृष्टि से सांवेदनशील होने के कारण यहां पर भूमि व जल संरक्षण की दृष्टि से भी रोपण आवश्यक होगा, ऐसे कार्य छोटे—छोटे जल खोलों के वानस्पतिक व अग्नियांत्रिक, संयुक्त उपचार से ही सफल हो सकेंगे, इनमें वृक्ष के विभिन्न वितानों (Storeys) के साथ—साथ झाड़ियों व घासों का व्यापक उपरिहार्य होगा;
- 4.11 जैविक विविधता के फलस्यकृप राज्य के वनों तथा इससे बाहर औषधि एवं सागन्ध पादप प्रबुर भाजा में पाए जाते हैं, परन्तु इनके रोपण के माध्यम से विकास की भी अहम भूमिका है, इन प्रजातियों को समय रूप से वृक्ष आदि प्रजातियों के साथ—साथ उगाने/विकास का प्रयास करना होगा;
- 4.12 कुटीर उद्योग तथा विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों में प्रतिस्थापन हेतु कई प्रजातियों यथा बांस, रेशा, जैटौफा, औषधीय व सागन्ध पौधों एवं घासों का विशेष महत्व है। प्रदेश में यथा उपयोगी क्षेत्रों में इनका रोपण किया जायेगा;
- 4.13 प्रदेश में वनों से जुड़ी हुई कई परम्परागत एवं बाद में विकसित संस्थाओं का इतिहास है, जो वन संरक्षण व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषतः वन पंचायतें सभी कार्यों में विशेष योगदान कर सकती हैं, इन्हें वृक्षारोपण कार्यों से सक्रिय रूप से जोड़ना लाभकारी होगा;

5. लक्ष्य

- 5.1 गारतीय वन संरक्षण की वर्ष 2003 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सकल मू—भाग के 64.81 प्रतिशत मू—भाग में अभिलिखित वन क्षेत्र हैं एवं 45.74 प्रतिशत मू—भाग वनाच्छादित है, यह राष्ट्र के वनावरण का 3.61 प्रतिशत है। विभिन्न वन आवरण की कैटेगरी के अनुसार 4002 वर्ग किमी² में अत्यन्त सघन वन (70% से अधिक वितान) 14420 वर्ग किमी² में सामान्य सघन वन (40 से 70% से अधिक वितान) है। इस प्रकार कुल 18422 वर्ग किमी² सघन वन है जो वन आवरण का 75.3 % है, 6043 वर्ग किमी² में खुले वन (10% से कम वितान) स्थित है, जो कुल वन आवरण का 24.7% है, इस प्रकार राज्य में वृक्ष आवरण (Tree cover) राष्ट्रीय वृक्ष आवरण का 1.07 प्रतिशत है;
- 5.1.1 उत्तरांचल में 64.81 प्रतिशत अभिलिखित वन क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 45.74 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अन्तर्गत Hill Areas के लिए 66% वनाच्छादन का लक्ष्य है;
- 5.1.2 इसी प्रकार प्रदेश के 14422 वर्ग किमी² सामान्य सघन वन को अत्यन्त सघन वन तथा 60.43 वर्ग किमी² खुले वन को सामान्य अथवा अत्यन्त सघन वन में परिवर्तित किया जा सकता है;

- ५.२ उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए आगामी १० वर्षों में सघन वनों के वर्तमान १४२२ वर्ग किमी^० क्षेत्रफल में बढ़ावदी कर २०००० वर्ग किमी^० की जा सकती है, उसी प्रकार रिकॉर्ड/अवनत रूप में उपलब्ध वन भूमि, गैर वन भूमि, निजी भूमि इत्यादि में अगले २० वर्षों में लगभग ५००० वर्ग किमी^० में वृक्षारोपण किया जा सकता है। इस हेतु सभी वित्तीय स्रोतों से योग्यता संसाधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा;

६. रणनीति

६.१ वन विभाग की भूमिका

वन विभाग, उत्तरांचल वन नीति, २००१ तथा वृक्षारोपण नीति, २००५ के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर नियोजन, समन्वयन तथा अनुश्रवण एजेंसी होगी, राज्य के जलागम विभाग, पंचायतीराज विभाग, ऊर्जा विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों की जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनके साथ वन विभाग के विभिन्न कार्यों का समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त सभी विभाग इस राबन्ध में वन विभाग से सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करेंगे,

६.२ वन आवरण में वृद्धि

प्राकृतिक पुनरोत्पादन/वनीकरण के भाव्यम से, भूदृष्टि को ध्यान में रखते हुए, हरित आवरण में वृद्धि हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाई जायेगी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वन सहयोग तथा विभिन्न विभागों के रामिलित प्रयासों से इसे क्रियान्वित किया जायेगा;

- ६.३ वृक्षारोपण के मूल उद्देश्यों एवं विद्यमान वनस्पति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के पूरे भू-भाग को निम्न प्रकार तीन क्षेत्रों (Region) में बांटा जा सकता है:

मैदानी / तराई भाबर क्षेत्र (Plains/Terai Bhabar Region) : इसमें मुख्यतः साल, शीशम, आदि के प्राकृतिक वन तथा यूकेलिप्टस, पीपल, सागौन आदि के वृक्षारोपण हैं, इन क्षेत्रों को प्राथमिकता पर उत्पादन वानिकी हेतु प्रबन्धित किया जायेगा,

मध्य हिमालय क्षेत्र (Middle Himalayan Region) : यह क्षेत्र सामान्यतया बीड, बांज आदि प्रजातियुक्त हैं, इन क्षेत्रों में विविध प्रयोजनों (Multi-Purpose Plantation) हेतु कार्य प्रबन्धित किया जायेगा;

उच्च रम्धलीय / उप-हिमालय क्षेत्र (High altitude/Subalpine Region) : इस क्षेत्र में जुनीपर्स, गोजपत्र आदि प्रजाति हैं, जिन्हें वन आवरण में वृद्धि हेतु लिया जायेगा;

६.४ रोपण हेतु प्रजातियों का वर्णकरण

अलग-अलग क्षेत्रों (Region) में पर्यावरणीय महत्व तथा स्थानीय उपयोगिता एवं विपणन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए स्थल की संपुष्कातानुसार विविध विभिन्न प्रजातियों का रोपण निम्न प्रकार किया जायेगा :

प्रजातियों का विवरण :

१. उच्च वितान (वृक्ष प्रजाति)	२० प्रतिशत
२. मध्य एवं निम्न वितान (आधिक प्रजातियों इधन, चारा, औषधीय, संगम्य फल, खाद्य-संपुरक (Food Supplement), बांस, वैकल्पिक इधन आदि)	८० प्रतिशत
गिरेशों का अनुपालन : प्रदेश में संचालित समस्त योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपणों में उपरोक्तानुसार वितान को ध्यान में रखते हुए प्रजातियों का ध्यान किया जायेगा;	
६.५ कृषि वानिकी : प्रदेश में पारिस्थितिक (इको सिस्टम) उपयुक्तता के आधार पर व्यापक एवं सघन वृक्षारोपण किया जायेगा, पर्वतीय क्षेत्र में गैर प्रकार्षीय वन उपज, जड़ी-बूटी तथा मैदानी क्षेत्र में औद्योगिक प्रजाति एवं संगम्य योग्यों को निजी भूमि में कृषिकरण हेतु बल दिया जायेगा;	
६.६ जनसाहमानिता : वृक्षारोपण के कार्य में निजी एवं राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों, स्वयंसेवी संस्थाओं, वन पंचायतों, ग्राम पंचायतों एवं समस्त सरकारी विभागों की सहमानिता सुनिश्चित की जायेगी;	
६.७ वन वाटिका / हरित पट्टी विकास : ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, पौराणिक स्थलों पर वन वाटिकाओं की स्थापना की जायेगी, इसके अतिरिक्त संडरों के किनारे वृक्षारोपण एवं मार्गों में छायादार एवं शोभाकार प्रजातियों के वृक्षारोपण द्वारा इन मार्गों पर हरित पट्टी विकसित कर हरित आवरण में वृद्धि की जायेगी;	

- 6.8 शहरी क्षेत्रों में नगरीय वन/राष्ट्रीय/राज्य मार्ग एवं नहरों के किनारे रोपण
- 6.8.1 **नगरीय वन (City Forest)** नगर निकायों के सहयोग से शहरों के मध्य/निकट स्थित वन भूमि पर वन पर्यायत का युठन कर वन संरक्षण तथा सबद्धन का कार्य किया जायेगा, जिसका प्रथोग नागरिक भ्रमण क्षेत्र के रूप में कर सके।
- 6.8.2 **हरित पट्टी (Green Belt)** औद्योगिक एवं नगरीय अवस्थापना के नियमों के अन्तर्गत हरित क्षेत्र तथा निकाय भूमि पर हरित क्षेत्र के विकास के लिए उपक्रमों तथा मौहल्ला समितियों का सहयोग लिया जायेगा,
- 6.8.3 **सड़कों के किनारे वृक्षारोपण** मैदानी क्षेत्र में पीपल बरगद आदि तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों से कपर की ओर नास आदि भू-दारण रोकने वाली प्रजातिया एवं नीचे की ओर उच्च वितान के वृक्ष रोपित किये जायेंगे,
- 6.9 **नदियों/नालों के किनारे रोपवन** ऐसे सबदनशील क्षेत्रों में उपर्युक्त भू-दारण रोकने वाली प्रजातियों के पौधों के रोपण पर बल दिया जायेगा;
- 6.10 **आरक्षित वनों में वृक्षारोपण** प्रस्तर 6.3 तथा 6.14 की नीति का पालन किया जायेगा
- 6.11 **अरक्षित वनों से बाहर वृक्षारोपण** प्रस्तर 6.3 की नीति का पालन किया जायेगा
- 6.12 **खाल बाल तथा तालों का विकास** प्रत्येक वृक्षारोपण के क्षेत्र में ग्रामी वाले खाल बाल तथा तालों के ऊपर सार्वजनिक अवलोकन (Public Access) का संरक्षण एवं विकास करना आवश्यक होगा तथा इनके आकार के अनुरूप उपलब्ध धनराशि का भाग इस कार्य के लिए आवंटित किया जायेगा।
- 6.13 **क्षेत्र विशिष्ट योजना (Site Specific Plan) :**
- सभी वृक्षारोपण योजनाओं में प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक ही विशिष्ट योजना (SSP) का निर्माण आवश्यक होगा। जो स्थान विशेष की आवश्यकताओं को देखता हुए निर्मित की जायेगी, इस योजना में क्षेत्र विशेष की मूल जानक री (Basic data) के अतिरिक्त उसकी समस्याएं समाधान तथा पर्यावरण विश्लेषण पर टिप्पणी होगी। इसका अनुमोदन संसद सत्र से कराया जायेगा,
- 6.14 **वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा :**
- 6.14.1 **आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा यथासम्भव वन पर्यायों के माध्यम से सायंकरात्मक जारी रखने के लिए उपलब्ध समिति नामित कर उनसे लम्बी अवधि की सुरक्षा का आपसी-करार (MOU) कराया जा सकता है।**
- 6.14.2 **आरक्षित वन क्षेत्रों के अन्तर्गत वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा पात्र वर्ष के लिए की जायेगी लेफिन रायेदानशील/मृदा रहित (Refractory) एवं यांत्रों के किनारे स्थित क्षेत्रों में दो शीय भूख्य वन संरक्षकों के अनुमोदन के पश्चात् राष्ट्रीय समिति नामित कर उनसे लम्बी अवधि की सुरक्षा का आपसी करार (MOU) कराया जा सकता है।**
- 6.14.3 **सुरक्षा हेतु यथासम्भव स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग जैविक सुरक्षा बाट आदि विधियों का उपयोग में लाया जायेगा जपरिहार्य स्थिति में ही दीवालबदी/तारबदी की जायेगी।**
- 6.15 **पौधशालाओं में आधुनिक पक्षति से पौध तैयार की जायेगी तथा समस्त वृक्षारोपण आधुनिक पौधालय तकनीक से उत्पादित गये उत्पादन वर्षावता युक्त पौधों से किये जायेंगे पूर्व में क्षेत्र के विभिन्न रुट-स्टॉक का अधिक उपयोग किया जायेगा जपरिहार्य प्रजातियों के बीज आदि की आपूर्ति रिल्फ्वा/अनुराघान द्वारा की जायेगी केवल प्रभागिक बीज ही उपयोग में लाया जायेगा।**
- 6.16 **वन पर्यायत पौधशालाओं का विकास** वन पर्यायों के अन्तर्गत ग्रामीणों के सहयोग से पौधशाला योग्यता की जायेगी जिनमें तकनीकी सहयोग वन विभाग हासा किया जायेगा,
- 6.17 **जल संवर्धन** प्रत्येक टाउन में समुचित नपी कायम रखने हेतु वर्षा जल रांचय साधना (Rain Water Harvesting) का बढ़ावा दिया जायेगा इस हेतु सञ्चय एवं केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा प्रतिपादित नवीनतम/प्रभागित विधियों को उपयोग में लाया जायेगा;
- 6.18 **वनीकरण हेतु उपलब्ध क्षेत्रों का सूचीकरण** राष्ट्रीय स्तर पर आौल इण्डिया सोयल एण्ड लैण्ड यूनिवर्सिटी (AISLU), द्वारा भूमि का इसकी उपयोगिता के अनुसार सर्वेक्षण जलागमवार किया गया है वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्रों का सूचीकरण करते समय इस सर्वेक्षण का लाम लिया जा सकता है, समस्त क्षेत्रों की अणीवार

सूची बनाकर प्रजातियों के वयन तथा दोनों की उपलब्धता की जायेगी और साथ ही अधिक सबेदनशील दोनों को प्राथमिकता के आधार पर वृक्षारोपण हेतु चिन्हित किया जायेगा, प्रत्येक वन प्रभाग में लैंड बैंक (Land Bank) का गठन करते हुए वृक्षारोपण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में उपलब्ध घनशस्त्रि का समन्वय किया जायेगा, यह हेतु प्रत्येक वर्ष घोषित किया जायेगा,

- 6.19 वन पचायतों में वृक्षारोपण प्रस्तर 6, 3 के प्राविधानों के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया जायेगा,
- 6.20 पारस्परिक एवं बरगद आदि प्रजाति के वृक्षों का रोपण पारम्परिक प्रजातियों जैसे बरगद, पीपल आदि के वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक पौधशाला में कुल उगाये गये पौधों का न्यूनतम पात्र प्रतिशत ऐसे पौधों के लिए निर्धारित किया जायेगा,
- 6.21 नैसर्गिक रूप से खाली स्थानों में वृक्षारोपण :
नैसर्गिक रूप से खाली स्थानों जैसे बुखाल, दलदली, सेत्र घास के मैदान, रोखड इत्यादि में वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा,
- 6.22 वन्य जीव प्रदण्डन के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण वन्य जीव सरकण की दीर्घकालीन रणनीति (Practise) के अनुसार वन्य जीव वासस्थल (Habitat) को विकसित करने के दृष्टिकोण से सबेदनशील वन हेतु के सामीप्ती जैसे वृक्षारोपण तदनुराग ही किया जायेगा। इसी प्रकार विभिन्न सरकित दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कारिठार (Carapalas) के निमोनाथ वृक्षारोपण किया जायेगा।
- 6.23 वनों की उत्पादकता बढ़ाना :
6.23.1 प्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु ऐसे प्रजातियों को लगाने (Introduce करने) हेतु अनुसाधान कुरा हारा गहन अध्ययन किया जायेगा अध्ययनापरात ही नई प्रजातियां लगाई जाएंगी।
- 6.23.2 विभिन्न वनोंपर आधारित उत्तोगों को प्रकाश की आपूर्ति हेतु यूक्सिप्टरा तथा पौपलर के वृक्षारोपण की उत्पादकता में वृद्धि के विशेष प्रयास किये जायेंगे इस हेतु अन्धी गुणवत्ता के पीछे तैयार करने के लिए अन्धी गुणवत्ता के प्रगतिशील वीज तथा बलोनल/टिश्यूकल्चर पौधों को अपनाया जायेगा।
- 6.23.3 रोपवनियों की उत्पादन सूखदा विधियों में सुधार एवं परिवर्तन लाने हेतु विभिन्न अन्य मॉडल्स का परीक्षण कर नवीनतम एवं प्रगतिशील विधियों को अपनाया जायेगा,
- 6.23.4 गुहालिप्टस रोपण दोनों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से रोपेशन को कम करने तथा सम्पूर्ण रोटेशन अधिक चार सम्पन्न सूखदा की व्यवस्था करने सबधी पहलू पर भी विज्ञार किया जायेगा।
- 6.24 प्राकृतिक वनों में अधोरोपण प्राकृतिक वनों में मुख्य प्रजाति के अलावा सह प्रजातियों एवं दोनों जैसे अधिक रूप से पाये जाने वाले पहले पौधों इफ्लियों का अधोरोपण किया जायेगा।
- 6.25 वृक्षारोपण सहित उपरोक्त निर्देशों को फौल्ड स्तर पर तकनीकी मार्गदर्शन हेतु विभाग हारा वृक्षारोपण महिला बनाकर प्रशारित की जायेगी।
- 6.26 शोध, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :
6.26.1 वन विभाग हारा जिक्कोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया बालिया इन्सटीट्यूट आदि के न्दीय अनुसाधान संस्थानों के साथ नियमित अन्तरालों पर सम्बन्ध हेतु बैठकें आदूता की जायेंगी ताकि इन शोध संस्थानों में जो नवीनतम शोध हो रहे हो उनसे वन विभाग परिचय रहे और ऐसे शोधों का यथोचित उपयोग कर सकें।
- 6.26.2 वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वीय का सघन दोरा कर वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण व अनुश्रवण करने ताकि अधीनस्थ द्वारीय अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्ध सुनिश्चित हो। तथा द्वारीय अधिकारी/कर्मचारी विभाग के लिए अधिक से अधिक सिद्ध हो सके व उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो।
- 6.26.3 वृक्षारोपणों की सफलता सुनिश्चित करने एवं नियमित युणात्मक सुधार हेतु विभागीय एवं केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य कराया जायेगा प्रथम 03 वर्ष तक वन विभाग/वन पचायत यह कार्य करेंगे प्रत्येक 03 वर्ष के बाद केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा।

6.26.4 अग्रिम विक्री एवं सुरक्षा : कामर्शियल प्लान्टेशन स्थलों (Commercial Plantation Sites) की विद्वाहन वर्ष तक प्रभावी सुरक्षा हेतु यथासम्बन्ध उपभोक्ता इकाइयों को अग्रिम विक्री (Advance Sale) की व्यवस्था लागू की जायेगी। इनकी लगातार प्रभावी सुरक्षा के लिए अन्य मॉडल भी विकसित कर आवश्यकतानुसार लागू किए जायेंगे।

7. राज्य वृक्षारोपण नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा :

राज्य स्तर पर वृक्षारोपण नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष मात्र ३० दिन एवं पर्यावरण मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी।

8. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 एवं उत्तरांचल वन नीति, 2001 से सम्बन्ध : राज्य वृक्षारोपण नीति, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 एवं उत्तरांचल वन नीति, 2001 के प्राविधानों के अधीन रहेगी।

डॉ० रणवीर सिंह,
सचिव।

न्याय अनुभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

16 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 25-सात-बी/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005-साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 12, सन् 1887) की धारा 14 और प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 9, सन् 1887) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महानहिम राज्यपाल, मात्र उत्तरांचल उच्च न्यायालय की संस्तुति पर शासन की अधिसूचना संख्या 18-सात-बी/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक 05 जुलाई, 2005 को निरस्त करते हुए रोशनाबाद, हरिद्वार में प्रत्यावर्तित किए गए अपर जिला जज/प्रथम दूरगामी न्यायालय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), राहायक सत्र न्यायाधीश/सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/हितीय दूरगामी न्यायालय, सहायक सत्र न्यायाधीश/सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/तृतीय दूरगामी न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं हितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों को दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 से पुनः रुक्की स्थानान्तरित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

प्रकीर्ण

18 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 26-सात-बी/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005-साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महानहिम राज्यपाल, मात्र उत्तरांचल उच्च न्यायालय की संस्तुति पर शासन की अधिसूचना संख्या 19-सात-बी/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक, 5 जुलाई, 2005 को निरस्त करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को सिविल न्यायालय परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार से दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 से पुनः रुक्की में स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

प्रकीर्ण

16 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 27—सात—बी/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005—पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66, सन् 1984) की धारा 3 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 38—एक (1)/न्याय विभाग/2004, दिनांक 15—04—2004 द्वारा लड़की (हरिद्वार) में सृजित पारिवारिक न्यायालय को मात्र उत्तरांचल उच्च न्यायालय की संस्तुति पर शासन की अधिसूचना संख्या 14—एक(11)/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक 5 जुलाई, 2005 को गिरस्त करते हुए दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 से सिविल न्यायालय परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार से युन: छड़की में रथानान्तरित करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं।

आशा से,

यू० सी० व्यानी,
सचिव।

गृह विभाग

अधिसूचना

(शक्ति)

21 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 3361/XX(1)—109/परी०/2004—राज्यपाल महोदय दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, रान् 1974) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तरांचल राज्य समिग्नित रिहित सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2004 की दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 में आयोजित परीक्षा के सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अवस्थापकों को, एतद्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक गजिस्ट्रेट कहलाएंगे और उन्हें ऐसी सभी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जो उक्त सहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती है, जिनका वे उन परीक्षा केन्द्रों की शीर्ष के अन्तर्गत होत्रों में उपयोग कर सकेंगे, जिनके वे केन्द्र अवस्थापक हैं।

आशा से,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3361/Home-1—109/Exam/2004, dated 21 December, 2005 for general information :

NOTIFICATION

(Power)

December 21, 2005

No. 3361/Home-1—109/Exam/2004—In exercise of the powers conferred under section 21 of the Code of Procedure 1973 (Act no. 2 of 1974), The Governor is hereby pleased to appoint the Superintendents of all the Examination Centres of Uttaranchal Public Service Commission for the Civil Services (Preliminary) Examination, 2004 being conducted on 22-12-2005, as Executive Magistrates, who shall be called Special Executive Magistrates, and confer all such powers on them as may be conferred on Executive Magistrates under the said Code, for that period, which they may use within the area of Examination Centres of which they are Superintendents.

By Order,

MANJUL KUMAR JOSHI,
Addl. Secretary.

चिकित्सा अनुमान-2

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 1786 /XXVIII-2-2005-323 /2005-एतद्वारा डा० (कु०) संगीता कठैत, चिकित्साधिकारी, राजकीय
संशुक्त चिकित्सालय, कोटड्हार, पौडी का दिनांक 09-02-2002 को विवाह के फलस्वरूप उनका नाम डा० (श्रीमति)
संगीता नेगी परिवर्तन करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा खे.

एस० राजू
सचिव।



ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ, ਉਤਤਰਾਂਚਲ

ਉਤਤਰਾਂਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਰੁਹਣੀ, ਸ਼ਨਿਵਾਰ, ਦਿਨਾਂਕ 07 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਈ0 (ਪੌਖ 17, 1927 ਸ਼ਕ ਸਾਲਾ)

ਮਾਗ 8

ਸੂਚਨਾ ਏਂਡ ਅਨੱਖ ਵੈਧਵਿਤਕ ਵਿਝਾਇਨ ਆਦਿ

ਸੂਚਨਾ

ਮੈਂ, ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸੌਨੀ ਪੁੜੀ ਸੀ ਅਤਰ ਸਿਹ ਸੌਨੀ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ, 2001, ਅਨੁਕੂਲਾਕ 0443738 ਦੇ ਅੰਕ—ਪੜ ਵ ਪ੍ਰਮਾਣ—ਪੜ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸੌਨੀ ਸਾਡੀ ਦਰਜ ਹੈ ਲੋਕਿਨ ਉਤਤਰਾਂਚਲ ਬੋਰਡ ਕੀ ਇੱਕਾਂਮੀਡਿਏਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ, 2004 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਾਕ 0004422 ਦੇ ਅੰਕ—ਪੜ ਵ ਪ੍ਰਮਾਣ—ਪੜ ਮੈਂ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸੌਨੀ ਕੇ ਰਥਾਨ ਪਰ ਤ੍ਰੁਟਿਵਸ਼ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿਹ ਅਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸੌਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਥਾ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂ ਇਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਨਾ ਜਾਏ।

ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸੌਨੀ, 30—12—05

ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸੌਨੀ

ਪੁੜੀ ਸੀ ਅਤਰ ਸਿਹ ਸੌਨੀ

196, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਨਿਕਟ ਹਨੁਮਾਨ ਮਨਿਦਰ,

ਰੁਹਣੀ।